>

Title: Need to give permission to legal mining in Goa.

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गोवा का एक बड़ा विषय माइनिंग के बैन का है। 18 महीने हो गए, गोवा की जो माइनिंग है, शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद उस माइनिंग पर बैन लगाया गया। इस माइनिंग के ऊपर कम से कम 40 परसैंट गोवा की आबादी का रोजगार चलता था। सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, लेकिन आज वहां की जो कम्पनियां हैं, वे कर्मचारी वर्ग को निकालने में लगी हैं। माइनिंग शुरू नहीं होने से वहां के ट्रक ड्राइवर और लेबर आदि को बहुत नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूं कि जो लीगल माइनिंग है, वह जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि कम्पनियों से जो लोगों को हटाना चाहते हैं, वे रुक जाएंगे और उनको रोजगार मिल जाएगा। इसलिए केन्द्र सरकार से मैं विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप हस्तक्षेप करके लीगल माइनिंग गोवा में फिर से शुरू करें।